

सम्पादकीय

रिश्तों का ताना-बाना

एक महिला बहुत-सी भूमिका एक साथ निभाती है- दादी मां, बेटी, बहन, बुआ, बहू, सास, भाभी आदि के रूप में। जब तक वह बेटी यानी अविवाहित होती है तो मायके में उसकी खास जिम्मेदारी नहीं होती और लाइ-प्यार में पलती है। बहुत-से माता-पिता उसको यह सिखाने में नाकाम होते हैं कि शादी के बाद उसकी भूमिका किस रूप में सफल और वजनदार होनी चाहिए और उसके लिए उसको कितनी सूझबूझ दी जाए। जीवन एक ऐसा प्रवाह है, जिसमें हम अचाई, बुराई, गुणावगुण आविष्कार के आवरण ओढ़े निरंतर बहते चले जाते हैं। समय अपने हिसाब से करवट बदलता रहता है। हम अपने कर्मों के चिह्न जीवन रूप से रास्ते पर छोड़ते चले जाते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार, उदास मानसिकता, जीवन को देखने-समझने-परखने का नजरिया ही हमारे समूचे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। महिलाएं हाँ या पुरुष, दोनों को ही जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सोच को परिवर्त्तन कराने की आवश्यकता होती है। देखा जाता है कि समाज में महिलाओं को बेचारी संबोधित करके उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। महिलाएं भी हमेशा पुरुष वर्ग को सते हुए अपने को ऊंचे स्थान पर रखने को चाहे-अन्यांशे लालायित रहती हैं, बिना यह विचारे कि हर जगह पुरुष गलत नहीं होता। बहुत से मामलों में उन्हें भी अपने अंदर झांकने के बहुत जरूरत होती है और अपनी गलतियों के परिणाम के जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना चाहिए। बदलाव का दौर है पुरुष या महिलाओं को अपने अंदर झांकते हुए खुद को दुरुस्त करने की कदम-कदम पर जरूरत है, ताकि ठीक से तालेमेल बना रहे और परिवारिक ढांचा न बिखरे। ऐसे में काफी चीजें ऐसे हैं, जो महिलाओं की गलत सोच और व्यवहार के कारण दुष्प्रभावित हो रही हैं। किसी भी परिवार या व्यक्ति की खुशी घर के बातावरण से ज्यादा जुड़ी होती है। परिवार की इकाई महिला के ईर्द-गिर्द ज्यादा घूमती है।

अगर महिला ने अपने आप में सुधार का बीड़ा जिम्मेदारी से नहीं उठाया तो समाज और परिवार में प्रतिकूल असर के पूरे-पूरे आसार हैं और कुछ दिनों में ऐसे परिवार के अस्तित्व को ग्रहण लगा दिखाई देगा। जहां महिलाएं सूधृ और समझदार होंगी, वे ही परिवार को ठीक से बचा पाने में कामयाब होंगी अन्यथा यह इकाई आज बिखराव की राह पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में उसके पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक परिवार की भूमिका के केंद्र का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण बहुत-सी चीजें उसके कारण उससे प्रभावित होकर घटित होती हैं और जिसका परिणाम परिवार की खुशहाली या बदलाली पर पड़ना लाजिमी है। एक महिला बहुत-सी भूमिका एक साथ निभाती है- दादी, मां, बेटी, बहन, बुआ, बहू, सास, भाभी आदि के रूप में। जब तक वह बेटी यार्नां अविवाहित होती है तो मायके में उसकी खास जिम्मेदारी नहीं होती और लाड़-प्यार में पलती है। बहुत-से माता-पिता उसके यह सिखाने में नाकाम होते हैं कि शादी के बाद उसकी भूमिका किस रूप में सफल और वजनदार होनी चाहिए और उसके लिए उसको कितनी सूझबूझ दी जाए। जन्मजात रूप से यह समझदार जाता है कि उसकी पढ़ाई-लिखाई करवा दो और जब जवान हो जाए तो उसकी शादी का अन्कूल प्रबंध कर दिया जाए। कम ही माता-पिता होते हैं, जो उसको शादी के बाद की भूमिका के लिए सही और वाजिब सीख देते हैं। शादी होती है तो ससुराल कई दहलीज पर कदम रखते ही लड़की की भूमिका जिम्मेदारी से जुड़ी मिलती है। उसकी हर गतिविधि और सोच पर ससुराल पक्ष की बारीक नजर होती है। अगर लड़की समझदार और मायके की समझाइश से अच्छा सीखी है तो कामयाब बहू बनने की राह पर चल पड़ती है, वही दूसरी तरफ अगर बिना तैयारी या परिपक्व सोच-विचार के सिर्फ शादी की रस्म के नाम पर ससुराल में चर्लां जाती है और वहां की जरूरत के हिसाब से तालमेल नहीं बैठती है, तो उसके गृहस्थ में आग लगना तय है। कुछ लड़कियां ससुराल में प्रवेश करते ही पति पर अपना अधिकार मान कर औरों के प्रति बेरुखी दिखाती हैं। निस्संदेह सबके साथ अनुकूल व्यवहार से ही रिश्तों को जीवंत और वजनदार बनाया जा सकता है। ऐसी लड़कियां सोची-समझी रणनीति के तहत परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ गलत तरीके से पति के कान भरना शुरू कर देती हैं। ऐसे में रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है। इसका असर रिश्तों के ताने-बाने पर पड़ता है। यह महिला के ऊपर निर्भर है कि वह ससुराल में समझदारी से परिवार को मजबूती से जोड़ती है या अपनी नासमझी की राह पर चल कर ससुराल को प्रयोगशाला बना कर खाई में धकेल देती है, जहां बस केवल संबंधों में तल्खी, विरोध, मनमुटाव, बिखराव या तलाक की गुंजाइश होती है, जिसमें दोनों पक्ष जिंदगी भर दुर्भाग्य, पश्चात्ताप या कसक लिए जीते दीखते हैं। इस सच के झुठलाया नहीं जा सकता कि काफी महिलाएं जरूरत से ज्यादा तारीफ की भूखी होती हैं, छोटी सोच रखती हैं और अपने सौंदर्य को भी हथियार मान लेती हैं। ऐसे में भ्रमवश अपने को जरूरत से ज्यादा उपयोगी, गुणी और त्याग की मूर्ति मान कर अंहंकारवश अपने अंदर जमी धूल को साफ करने की कोशिश नहीं करती। परिवार की मजबूती महिलाओं की उदारता, सब्र, परिपक्व सोच सूझ-बूझ आदि पर टिकी होती है। रिश्तों की डोर में अगर इन गुणों से गृहस्थी गुंथी होंगी तो मजबूत धागे से जुड़े संबंधों की जाकर करार करना पर निर्भर रहेगी।

कोविड-19 के इलाज के लिए ऐंटीवायरस गोली तैयार

मुकुल व्यास

गालिया का रूप में ला जा सका है पटाइट्स से सा आ एड्स जस अनक वायरल इंफेक्शनों के इलाज के लिए ऐटीवायरल दवाओं का प्रयोग पहले से हो रहा है। मसलन इन्फूजंगा के इलाज के लिए टैमीफु काफी चर्चित दवा है। लोगों और जानवरों में वायरस के संक्रमण के इलाज और निगरान के लिए विकसित दवाएं अलग-अलग ढंग से काम करती हैं। लेकिन इनमें फेरबदल कर इनका प्रयोग संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये दवाएं स्वस्थ कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को अवरुद्ध कर सकती हैं या शरीर में सक्रिय वायरस की मात्रा कम कर सकती है। कोविड के लिए इस समय तीन ऐटीवायरल दवाएं चर्चा में हैं। इनमें से एक दवा मोलनुपिराविर का क्रिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। शेष दो के क्रिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। मोलनुपिराविर को मर्क एंड कंपनी और रिजॉर्क बायो थेरेप्यूटिक्स ने विकसित किया है। दो अन्य ऐटीवायरल दवाओं में फाइजर की पीएफ 07321332 नामक दवा तथा रोश और एटी फार्मास्युटिकल्स की एटी-527 नामक दवा शामिल है। मर्क ने अपनी दवा के क्रिनिकल ट्रायल के अंतरिम परिणामों का ऐलान कर दिया है। इस कंपनी का दावा है कि मोलनुपिराविर कोविड से मौत का रिस्क आधा कर देती है। कंपनी इस दवा के आपात उपयोग के लिए आवेदन करने जा रही है। यदि इसे अनुमति मिल गई तो यह दुनिया में कोविड की पहली ऐटीवायरल दवा होगी। यह दवा मूल रूप से इन्फूजंगा के इलाज के लिए विकसित की गई थी। ऐटीवायरल दवाएं मानव कोशिकाओं में वायरस के विस्तार की क्षमता में अवरोध पैदा करती हैं। मोलनुपिराविर वायरस के आनुवंशिक कोड में त्रुटियां उत्पन्न कर उसे शरीर में फैलने से रोकती हैं। इसके उपयोग से मरीज का वायरस लोड कम होता है और संक्रमण का समय घटता है। यह दवा खतरनाक इस्पन रिस्पोन्स को भी रोकती है जिसकी वजह से कोविड गंभीर रूप ले लेता है। अभी तक कोविड के इलाज के लिए सिर्फ एक ऐटीवायरल दवा रेमडोसीवीर को ही मंजूरी मिली है। लेकिन यह उन मरीजों को इंट्रावेनस इंजेक्शन से दी जाती है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं। बीमारी के शुरू में इसका व्यापक इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी तरफ नई ऐटीवायरल दवाओं की गोलियों के रूप में पैकिंग की जा सकती है। चूहों पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन में पता चला कि मोलनुपिराविर? कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न शुरुआती बुखार को रोक सकती है। दवा का फॉर्म्युला अमेरिका की एमरी यूनिवर्सिटी में खोजा गया जिसे बाद में रिजॉर्क और मर्क ने हासिल कर लिया।

सट कर रहे या हट कर, खतरा दोनों जगह

निशिकांत ठाकुर

पिछले कुछ दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में कई ताबड़तोंसे नियन्य देते हुए भारतीय जन मानस को यह विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया है कि उनके हृदय में यह विश्वास- संतोष बना रहे कि अभी भारतीय न्यायपालिका नींद से बोझिल सरकार को जगाने तथा भ्रष्ट नौकरशाहों लिए न्याय का न्यायिक डंडा तैयार कर रखा है। इसी क्रम में सत्तासीन राजनेताओं के साथ तालमेल बैठाकर गलत कार्यों में लिप्त पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस श्रेणी में आने वाले पुलिसकमिच्यों को संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल भेज देना चाहिए मुख्य न्यायमूर्ति ने छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अधिकारी गुरुजिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध संपत्ति और राजद्वेष जैसी धाराओं में आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से राहत दी। साथ ही जांच में सहयोग के लिए कहा। पिछली सरकार में एंटी करण्शन ब्यूरो के मूर्खिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करेगा तो उसे इस तरह वे आरोप झेलना ही पड़ेंगे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, 'आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते। आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यहीं होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं तो आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

सत्तासीन राजनेताओं के करीबा पुलिस आधिकारी किसी को किसी से भी आरोप में जेल में डलवाते हैं और उन्हीं के करीबियों को, जो मदद करने के लिए ऊपर बैठे हैं, किसी अपराधी को दोषमुक्त साबित करके फूलमाला से लादकर समाज के सामने हीरो के रूप में कद ऊंचा कर सकती है, क्योंकि पुलिस का सत्ता से गठजोड़ अब पुरानी बात हो गई है। इस गठजोड़ में पुलिस हमेशा फायदे में रहती है। कहा जा सकता है कि सत्ता किसी की हो, पुलिस के दोनों हाथ में लहू होता है। जैसे-जैसे राजनीति में गिरावट आई, वैसे-वैसे यह गठजोड़ और मजबूत होता गया। मुंबई में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो या यूपी में

अनेक जिलों में हाल में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामले हों या अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई, सब सत्ता के चश्मे के नंबर बदलने वाली भर है। पुलिस सत्ता के इशारे को बखूबी समझते हुए उसका दस्तावेजीकरण भी कर देती है। यह अलग बात है कि कई बार अदालत पहुंचने के साथ ही इनका भांडा फूट जाता है। अब सिस्टम में इतना घुल गुल चुका है कि इलाज मुश्किल है। एक थानेदार कहते हैं- आपके पास दो हजार के दो जाली नोट मिले। अगर जेल भेजना है तब पुलिस लिखेगी- पत्रकरिता की आड़ में यह आदमी जाली नोटों का कारोबार करता है। यह काम वर्षों से चल रहा है। इसका गिरोह नेपाल तक पसंद हुआ है। छोड़ना हुआ तो लिखा जाएगा- दो हजार के ये दो नोट गलती इनकी जेब में आ गए थे। यह समाज के सम्मानित व्यक्ति है और इनका आम शोहरत भी अच्छी है। ऐसा निश्छल व्यक्ति जाली नोटों के सौदागर हो ही नहीं सकता। जुर्म एक, लेकिन पुलिस का विवेक यहां बहुमत्वपूर्ण भूमिका में है। इसी भूमिका की पुलिस खाती आ रही है।

मालगांव धमाका (2008) की स्पेशल प्रूसिक्युटर रोहिणी सालियर ने वर्ष 2015 में आरोप लगाया था कि इस हमले के अभियुक्तों को लेकर नरमी बरतने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। रोहिणी ने एनआईए एसपी सुहास वर्क पर यह आरोप लगाया था। रोहिणी ने कहा था कि ऐसा केस को कमज़ोर बनाने के लिए किया गया, ताकि सभी अभियुक्त बरी हो जाएं। इस ब्लास्ट में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभियुक्त है। रोहिणी ने एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एनडीए सरकार आने के बाद मेरे पास एनआईए के अधिकारियों वाले फोन आया। जिन मामलों की जांच चल रही थी, उनमें हिंदू अतिवादियों पर आरोप थे। मुझसे कहा गया वे बात करना चाहते हैं। एनआईए उस अधिकारी ने कहा कि ऊपर से इस मामले में नरमी बरतने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि पिछले 8 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने ईडी को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लाइंग मामले में मुर्बई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाला से पूछताछ की जाजात दी थी। सचिन वाजे को एंटीलिया केस और ठाकुर के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी व मुर्बई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे को पत्र लिख तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 10 करोड़ वसूली करवाने का आरोप लगाया था। गृहमंत्री देशमुख ने सचिन को बार व रेस्टरां से 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह वसूली का लक्ष्य दिया।

था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों से इन्कार किया था। उपरोक्त सभी कार्यवाही पुलिस पर राजनीतिज्ञों के दबाव का ही परिणाम है, भले ही इसे आज कोई स्वीकार करे या न करे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, 'पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होती है।' यह परेशान करने वाला ट्रैड है। इसे रोकने की जरूरत है। सीजेआई रमण ने आगे कहा, 'जब सरकार बदलती है तो पुलिस अफसरों को ऐसे आरोपों का सामना करना ही पड़ता है। यह देश में नया चलन है। उन्होंने कहा, 'इस सबके लिए खुद पुलिस अफसरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद भी सत्तासीन राजनीतिज्ञों से अपनी दूरी बनाकर संविधान प्रदत्त अधिकारों का वह उपयोग पुलिस के आला अधिकारी ऐसा करेंगे। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को पिछले महीने 27 अगस्त को लखनऊ में गिरफतार किया गया था। ठाकुर पर मुख्यार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। जिस लड़की ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था, उसकी मौत हो चुकी है। पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अपनी गिरफतारी को अवैध ठहराते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी अब एक मुकदमा दर्ज कराया है। अमिताभ ठाकुर का यह मुकदमा यूपी के नौ अफसरों के खिलाफ है, जिसमें ईडीशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी भी शामिल हैं। अमिताभ ठाकुर ने इन अफसरों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बदला लेने की नीति से उन्हें नौकरी से निकाला गया, साथ ही फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया। अब सच क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर की जानकारी यह है कि अमिताभ ठाकुर को किसी भी सत्तासीन राजनेताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। लिहाजा, वह सत्ता की गलियारों में पीछे होते गए और अब उनका हाल यह हो गया कि पुलिस उन्हें घसीटकर घर से ले गई। ऐसे में सगल यह है कि यदि सत्तासीन को अधिकारी अपना आका नहीं मानेंगे तो क्या वह अपना भी वही हाल कराएंगे जो हाल अमिताभ ठाकुर का लखनऊ में हुआ। सर्वीच्य न्यायालय को इस पर भी सख्त आदेश देने की जरूरत है।

चुनाव जीतने के लिए भाजपा धड़ाधड़ जो भी फैसले ले रही है वह सब उल्टे पड़ जा रहे हैं

स्वदेश कुमार

यह और बात है कि समय के साथ योगी के फैसलों पर अब ज्यादा उंगलियां उठने लगी हैं, जिस तरह से योगी सरकार ने लख्मीमपुर कर्मचारी घटना को हैंडिल किया उससे भी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के बीच नाराजगी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के बीच क्या सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। जानकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों संगठन और सरकार के हुक्मरानों द्वारा ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें सरकार और पार्टी के उद्धार की जगह आपसी वैमस्य नजर आता हो। इसीलिए तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी कौन मजबूरी आ गई थी, जो उसे पिछड़े समाज के वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए एक दलित नेत्री और पूर्व सांसद प्रियंका रावत का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी के पास उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या जैसे कहावत पिछड़ा समाज का नेता मौजूद है। केशव प्रसाद को कोई कैसे भूल सकता है जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व अक्टूबर 2018 में प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग समाज सम्मेलन कराकर बीजेपी के पक्ष में महील बनाया था। तब पिछड़ा वर्ग के वोटरों ने दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था।

केशव प्रसाद मौर्या की तरह ही पूर्व बसपाई और अब योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्या को बीजेपी में इंटी ही इसलिये मिली थी क्योंकि उनकी पिछड़ा वर्ग समाज में काफी अच्छी और मजबूत पकड़ थी। बीजेपी चाहती है तो केशव प्रसाद मौर्या के साथ स्वामी प्रसाद मौर्या का भी इस्तेमाल करेंगे को मनाने के लिए कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों बीजेपी आलाकमान ने पिछड़ा को मनाने की जिम्मेदारी किसी पिछड़ा समाज के नेता की जगह अपनी दलित नेत्री और बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत के कंधों पर डालना ज्यादा उचित समझा। बीजेपी ने प्रियंका रावत के कंधों पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी डाली है। यहीं से पिछड़ा समाज की नाराजगी बीजेपी से कम होने की बजाए बढ़ने लगी है। जिस तरह से प्रियंका रावत ने पिछड़ा को मनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए हैं, उसमें कई खोट नजर आ रह है। ऐसा लगता है प्रियंका रावत ने पिछड़ा वर्ग समाज का आंदोलन करने से पूर्व पिछड़ा समाज के बारे में कोई अध्ययन ही नहीं किया। अगर ऐसा न होता तो प्रियंका रावत पिछड़ा समाज की 79 जातियों में से सिर्फ 17 जातियों का 'पिछड़ा वर्ग सम्मेलन' नहीं करती। इतना ही नहीं जिन 17 पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता दी गई है, उसमें से कई जातियों का तो बजूद ही बहुत सीमित है, जबकि तमाम ऐसी जातियों को छोड़ दिया गया है जिनका अच्छी खासी आबादी है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्रियंका रावत है कौन और इनकी संगठन में क्या हैसियत है। अगस्त 2021 से पूर्व प्रियंका की पार्टी में कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 22 शासकों को आमंत्री बतानीश्वित रीत चलाने की तो उसमें सबसे जौनपुर

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष न अपना कार्यकारण में आठ दलत नाटव को जगह दी है जिसमें पासी जाति से संबंध रखने वाली प्रियंका सब युवा थीं। यह तब हुआ जबकि 219 में लोकसभा का टिकट करने वाला नाराज भाजपा की सांसद प्रियंका रावत ने बगावती सुर अखियार कर रखे थे। प्रियंका का अपना कोई खास जनाधार भी नहीं है। हाँ, विवाह से उनका गहरा नाता है। एक बार प्रियंका रावत को दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पर्स में रखी छुरी के साथ पकड़ा गया था। इस पर अपनी गलती मानने की बजाए प्रियंका रावत एयरपोर्ट के स्टाफ को ही धमका लगी थीं। इसी प्रकार दिसंबर 2017 में सांसद प्रियंका सिंह रावत वीडियो एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी को कथित रूप से धमकाते हुए कैमरे में कैद हुई थी। इस घटना का फुटेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल मीडिया पर गायरल हो गया था। घटना सफदरगंज थानाक्षेत्र चौला गांव में सरकारी जमीन पर राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव गवलों से हाए विवाद से जड़ी थी। तब भाजपा

सरकार आर सगठन का साथ पर बड़ा ता लग हा रहा हा। समाज के कई वर्गों के वोटों के बीच भी मैसेज सही नहीं जा रहा है। पहले गुजरात के पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को जिस तरह से अपमानित किया गया था, अब वैसे ही केशव प्रसाद मौर्या आहत नजर आ रहे हैं। केशव के लिए यह स्थिति काफी परेशान करने वाली होगी कि उनके रहते पिछड़ों को मनाने की जिम्मेदारी किसी दलित नेता की कंधों पर डाली जाए। इसका क्या रिएक्शन होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, परंतु इस तरह के फैसलों से सीएम योगी अदित्यनाथ की साथ पर भी चोट तो पहुंच ही रही है। वैसे भी योगी-केशव प्रसाद मौर्या के बीच संबंध कभी अच्छे नजर नहीं आते हैं।

2017 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्या का जनता के सामने ऐसे पेश किया था, जैसे यदि बीजेपी की सरकार बनेगी तो केशव ही सीएम होंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो अद्यानक योगी का पर्दापण हुआ और वह सीएम बन गए। केशव खुन का घूंट पीकर डिटी सीएम बनकर ही रह गए। इसी के चलते योगी और केशव के रिश्ते कभी मधुर नहीं रह पाए। इस बात का अहसास तब एक बार फिर हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिटी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के पिता जौ की कौशलग्नी में हुई मौत के समय केशव के घर जाकर सांत्वना देना उचित नहीं समझा। इस पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी आलाकमान को भी इस बात की जानकारी हुई तो वह डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आई। 21 जून 2021 को योगी को केशव प्रसाद के यहां जाना ही पड़ा। साढ़े चार साल में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री डिटी सीएम के घर गए थे, जबकि दोनों के आवास में सिर्फ 100 मीटर की ही दूरी है। मुख्यमंत्री लंच के लिए गए थे। इस मौके पर उनके साथ आरएसएस के सह सर कार्यवाह कृष्णगोपाल, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित कामेटी के सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केशव मौर्या के घर पर लंच के सियासी मतलब निकाले गए और यह माना गया कि बीजेपी इस मुलाकात से अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को संदेश देना चाह रही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीकठाक चल रहा है। यह और बात है कि समय के साथ योगी के फैसलों पर अब ज्यादा उंगलियां उठने लगी हैं, जिस तरह से योगी सरकार ने लखीमपुर की घटना को हैंडिल किया उससे भी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के बीच नाराजगी नजर आ रही है। पार्टी के एक सीनियर लीडर का कहना था कि राजनीति अवधारणा पर चलती है। हमेशा सही-गलत के आधार पर फैसला नहीं लिया जाता है, जब जनता के बीच यह धारणा आम हो रही थी कि लखीमपुर कांड में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र की भूमिका संदिधि नजर आ रही है तो उसे गिरफतार करने में इतनी देरी क्यों की गई जिससे विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान यहां गौर करने वाला है। देव ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने यह कहकर काफी कुछ संकेत दे दिया कि किसी नेता को अपनी छिप ऐसी नहीं बनाना चाहिए जिससे जनता उनसे डरे। स्वतंत्र देव का इशारा लखीमपुर ज़रीनी स्टेट टीवी भी था।

खोरा काड़ की ओर हो था। बात इससे आगे बढ़कर की जाए तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तब से लेकर आज तक यूपी के सांसदों-विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का एक ही रोना रहा है कि योगी सरकार में जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। योगी को अपने नेताओं से अधिक भरोसा ब्यूरोफ्रेसी पर है। योगी ने 'टीम 11' बना रखी है। यही टीम 11 हर बड़ा फैसला लेती है। यह 'टीम-11' और कोई नहीं 11 सीनियर आईएएस अधिकारी है। इनकी सलाह पर ही योगी महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, इसी के चलते बीजेपी के नेता और जनप्रतिनिधि करीब पांच सालों तक मूलदर्शक बने रहने को मजबूर रहे। इन नेताओं की न जिलाधिकारी कार्यालय में सुनवाई होती थी, न थाने-चौकी पर कोई इनकी सुनता था। क्षेत्र में कौन से विकास कार्य कैसे चलने और पूरे किये जाएंगे, यह भी अधिकारी ही तय करते हैं, जिसके चलते उत्तर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को जनता के कोपभाजन का भी शिकार बनना पड़ता है। अपनी व्यथा कई बार यह सांसद-विधायक और सभासद आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का। ऐसा ही कुछ बीजेपी के 17 अक्टूबर से प्रस्तावित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में देखने को मिल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी न जाने क्या सोच कर दलित नेत्री प्रियंका रावत के कंधों पर डाली गई है। सब गल यह भी उठ रहा है कि यदि प्रियंका रावत के ऊपर जिम्मेदारी डाली ही गई थी तो प्रियंका को पिछड़ा समाज के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए था। यदि वह उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से ही जानकारी जुटा लेती तो काफी हद तक फजीहत से बच जाती। उम्मीद है बीजेपी आलाकमान समय रहते अपनी गलती में सुधार कर लेगा, वर्ना पिछड़ा वर्ग समाज की नाराजगी बढ़ती ही जाएगी।

